



गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 311

दि. 15.03.2026,

रविवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

ड्रोन, होर्मुज और जिद की जंग: ईरान के सामने उलझती जा रही ट्रंप की रणनीति

जीएनएस)। तेहरान/वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में शुरू हुआ अमेरिका-ईरान टकराव अब तेजी से ऐसे युद्ध में बदलता दिखाई दे रहा है जिसकी अवधि और परिणाम दोनों ही अनिश्चित होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही आक्रामक विदेश नीति के संकेत दे दिए थे। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को हटाने के अभियान के बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान में भी नेतृत्व को समाप्त कर सत्ता परिवर्तन की रणनीति अपनाते का प्रयास किया। फरवरी के अंत में तेहरान पर किए गए हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei की मौत के बाद वाशिंगटन को उम्मीद थी कि ईरान की सत्ता तेजी से कमजोर हो जाएगी और कुछ ही हफ्तों में युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में दिखाई देने लगेगा। लेकिन घटनाक्रम उल्टा होता नजर आ रहा है। जिस संघर्ष को ट्रंप कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला युद्ध बता रहे थे, वह अब धीरे-धीरे लंबा और जटिल होता जा रहा है। अमेरिकी रणनीति का सबसे बड़ा आधार यह था कि नेतृत्व खत्म होते ही ईरान की राजनीतिक व्यवस्था बिखर जाएगी और जनता सड़कों पर उतरकर सत्ता

परिवर्तन का रास्ता बना देगी। लेकिन तेहरान में ऐसा नहीं हुआ। खामेनेई की मौत के बाद सत्ता तेजी से उनके बेटे Mojtaba Khamenei के हाथों में चली गई और ईरानी व्यवस्था पहले से अधिक सख्त होकर सामने आई। यह स्थिति वाशिंगटन के लिए अप्रत्याशित थी, क्योंकि उसकी उम्मीद थी कि नेतृत्व खत्म होने के बाद सत्ता संघर्ष शुरू होगा और देश भीतर से कमजोर पड़ जाएगा। इसके उलट ईरान की सत्ता संरचना ने खुद को संगठित करते हुए युद्ध की तैयारी और तेज कर दी। युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक Strait of Hormuz पर दिखाई दिया है। फारस की खाड़ी से गुजरने वाला यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति की धुरी माना जाता है। ईरान ने इस मार्ग पर नियंत्रण मजबूत करते हुए जहाजों के लिए परमिट प्रणाली लागू कर दी और कई क्षेत्रों में नौवहन को सीमित कर दिया। इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए यह स्थिति बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इस मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित रखना अत्यंत महंगा और जोखिम भरा साबित हो



सकता है। ईरान के सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन और मिसाइलों अमेरिकी नौसेना के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं। ईरान की ड्रोन शक्ति इस युद्ध का सबसे निष्पक्ष तत्व बनकर उभरी है। पिछले एक दशक में तेहरान ने कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइलों के बड़े नेटवर्क को विकसित किया है। शाहद श्रृंखला के ड्रोन हजारों की संख्या में तैयार किए गए हैं, जिन्हें भूमिगत टिकानों से संचालित किया जा सकता है। इन ड्रोन की मारक क्षमता भले ही अत्यधिक आधुनिक हथियारों जितनी न हो, लेकिन उनकी संख्या और कम लागत उन्हें अत्यंत प्रभावी बना देती है। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यही कारण

कई बार ईरानी वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाकर उसके कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेहरान ने हर बार नई रणनीति के साथ वापसी की। इस युद्ध में इजरायल की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इजरायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu लंबे समय से ईरान को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते रहे हैं। इजरायल की रणनीति अक्सर विरोधी संगठनों या नेताओं को सीधे निशाना बनाने की रही है। हमला और हिज्बुल्लाह जैसे संगठनों के कई शीर्ष नेताओं को खत्म करने की नीति इसी रणनीति का हिस्सा रही है। लेकिन ईरान कोई संगठन नहीं बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र है, इसलिए वहां नेतृत्व खत्म करने की नीति उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी अपेक्षा की गई थी। खामेनेई की मौत के बाद वैश्विक शिया समुदाय में भी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। ईरान का सर्वोच्च नेता केवल देश का राजनीतिक प्रमुख ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए धार्मिक नेतृत्व का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में इस हमले को केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि धार्मिक

और भावनात्मक चुनौती के रूप में भी देखा गया। इससे ईरान के भीतर बदले और प्रतिरोध की भावना और मजबूत हुई है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक समस्या यह है कि इस युद्ध का स्पष्ट लक्ष्य अब तक तय नहीं हो पाया है। शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि इस संघर्ष का उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों के बयान इस मुद्दे पर अलग-अलग नजर आते हैं। सत्ता परिवर्तन की बात धीरे-धीरे पीछे चली गई है और चर्चा केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रह गई है। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका इसे किस प्रकार रोकना चाहता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था International Atomic Energy Agency के अनुसार ईरान के पास अभी भी बड़ी मात्रा में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। यह भंडार अत्यंत गहराई में सुरक्षित टिकानों में रखा गया है, जिन्हें नष्ट करना आसान नहीं है। अमेरिकी बमबर्षक विमानों द्वारा किए गए हमलों के बावजूद इन टिकानों का पुरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन्हें पूरी तरह नष्ट करना है तो जमीन पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसमें सैनिकों की तैनाती आवश्यक होगी। लेकिन ट्रंप लंबे समय से विदेशी युद्धों में अमेरिकी सैनिक भेजने के विरोधी रहे हैं, इसलिए यह निर्णय उनके लिए राजनीतिक रूप से भी कठिन होगा। युद्ध का एक और पहलू अमेरिकी घरेलू राजनीति से जुड़ा है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने बार-बार कहा था कि वे अमेरिका को दूसरे देशों के युद्धों में नहीं उलझने देंगे। लेकिन अब वही अमेरिका एक बड़े सैन्य अभियान में फंसता दिखाई दे रहा है। यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है और इसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत बढ़ती है या तेल की कीमतों में तेज उछाल आता है, तो इसका असर अमेरिकी मतदाताओं पर भी पड़ सकता है। युद्ध की शुरुआत में ट्रंप और नेतन्याहू को उम्मीद थी कि ईरान की जनता सरकार का यह टकराव अब केवल दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा ऐसा संकट बन गया है जिसका प्रभाव आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।

है कि बाहरी खतरे की स्थिति में अक्सर ऐसा ही होता है, जब जनता अपने मतभेदों को कुछ समय के लिए किनारे रख देती है। अब यह युद्ध केवल सैन्य शक्ति का संघर्ष नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और आर्थिक क्षमता की परीक्षा बन गया है। ईरान लंबे समय तक संघर्ष झेलने की क्षमता रखता है और उसने अपनी सैन्य संरचना भी उसी आधार पर विकसित की है। दूसरी ओर अमेरिका को अपने वैश्विक हितों, सहयोगियों और घरेलू राजनीति के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है। यही कारण है कि जिस युद्ध को कुछ ही दिनों में समाप्त करने का दावा किया गया था, वह अब अनिश्चितता का यह टकराव अब केवल दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा ऐसा संकट बन गया है जिसका प्रभाव आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।

कर्नाटक में उपचुनाव की आहट तेज, कांग्रेस ने बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण सीटों के लिए शुरु की व्यापक तैयारी

जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा फिर चुनावी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। राज्य की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इन उपचुनावों के लिए Indian National Congress पूरी तरह तैयार है और पार्टी ने चुनावी मोर्चे पर अपनी तैयारियों को लगातार अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी संगठन पूरी तरह सक्रिय है और चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। दरअसल इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की नौबत इसलिए आई है क्योंकि यहां के दो वरिष्ठ विधायकों के निधन के बाद ये सीटें रिक्त हो गई थीं। बागलकोट सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व विधायक H. Y. Meti के निधन से यह सीट खाली हुई, जबकि दावणगेरे दक्षिण सीट के विधायक Shamanur Shivashankarappa



के निधन के बाद वहां भी उपचुनाव की स्थिति बन गई। इन दोनों नेताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में काफी प्रभाव था और उनके निधन से स्थानीय राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। अब इन सीटों पर नए प्रतिनिधियों के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्थानीय संगठन से फीडबैक लेकर चुनावी रणनीति तय की जा रही है। उनके अनुसार इन सीटों पर कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है और

पार्टी को विश्वास है कि जनता का समर्थन इस बार भी कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास और पार्टी की नीतियों की परीक्षा भी होता है। उम्मीदवार चयन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों सीटों के लिए संभावित नामों पर चर्चा चल रही है। राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता संभावित उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। इसके बाद अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। सिद्धरमैया ने यह भी स्पष्ट किया कि उम्मीदवार का चयन करते समय स्थानीय लोकप्रियता, संगठन के प्रति समर्पण और जीतने की क्षमता जैसे सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। बागलकोट सीट को लेकर खास तौर पर दिलचस्पी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि

दिवंगत विधायक एच. वाई. मेट्टी के परिवार के सदस्य भी इस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और उन्हें संभावित दावेदारों में माना जा रहा है। सिद्धरमैया ने कहा कि स्थिति का चुनाव लड़ने की इच्छा रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी दावेदारों के बारे में विचार करेगी और फिर ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे पार्टी को अधिकतम लाभ मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव अक्सर किसी भी सरकार और सत्तारूढ़ दल के लिए जमनात की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होते हैं। हालांकि यह चुनाव केवल दो सीटों के लिए होगा, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत काफी दूर तक जा सकते हैं। यदि कांग्रेस इन सीटों पर जीत दर्ज करती है तो इससे राज्य में उसकी स्थिति और मजबूत होने का संदेश जाएगा। वहीं विपक्षी दल भी इन सीटों पर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह भी बताया कि उपचुनाव खास तौर पर दिलचस्पी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि

तमिलनाडु में चुनावी सरगमी तेज: नई पार्टियों की एंट्री से सियासी मुकाबला रोचक

जीएनएस)। चेन्नई। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त होने वाला है और परंपरा के अनुसार चुनाव आयोग आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने से चार से छह सप्ताह पहले मतदान कराता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि राज्य में मतदान अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। चुनावी माहौल बनते ही सभी प्रमुख दलों ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, वहीं दो नई राजनीतिक पार्टियों की एंट्री ने इस बार के चुनाव को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म अभिनेता Vijay की नई पार्टी Tamizhaga Vetri Kazhagam को लेकर हो रही है। अभिनेता विजय, जिन्हें उनके प्रशंसक 'थलापति' के नाम से जानते हैं, ने अपनी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। उनकी पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि टीवीके

तमिलनाडु की राजनीति में किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत आजमाना चाहती है। विजय की पार्टी ने एक और महत्वपूर्ण संदेश देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ किसी भी प्रकार का चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के संयुक्त महासचिव Nirmal Kumar ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा उनकी पार्टी की वैचारिक विरोधी है और इस वजह से दोनों दलों के बीच किसी प्रकार के चुनावी समझौते की संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में जो खबरें गठबंधन की संभावना को लेकर चल रही हैं, वे केवल अटकलें हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस चुनाव में दूसरी नई पार्टी के रूप में मुख्यमंत्री J. Jayalalitha की करीबी सहयोगी और All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam से निष्कासित नेता V K Sasikala ने भी अपने राजनीतिक सफर की नई शुरुआत की है। शशिकला ने 13 मार्च को अपनी नई पार्टी All India Puratchi Thalavaivar Makkal Munnetra Kazhagam के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 40 सीटों

पर उम्मीदवार उतारेंगी। शशिकला ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह और झंडे को भी सार्वजनिक किया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह नायरिल के पेड़ों वाला खेत है, जबकि पार्टी के झंडे पर तमिल राजनीति के तीन प्रमुख नेताओं की तस्वीरें शामिल की गई हैं। इनमें C N Annadurai, M G Ramachandran और जयललिता की तस्वीरें हैं। इन तीनों नेताओं को तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ आंदोलन और क्षेत्रीय राजनीतिक परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शशिकला ने यह भी संकेत दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव अकेले नहीं लड़ेगी, बल्कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने की कोशिश करेगी। राज्य की मुख्यधारा की राजनीति में भी चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। Indian National Congress ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है। पार्टी के अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने राज्य में चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रदेश स्तर की कई समितियों को मंजूरी दी है। इनमें से सेल्वपेरुंगुई की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति का गठन भी शामिल है। कांग्रेस ने इसके अलावा चुनाव प्रचार समिति, चुनाव घोषणापत्र समिति, चुनाव

ओडिशा राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों से गरमाई राजनीति

जीएनएस)। कटक। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल अतिसरमिलित हो गया है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष Naveen Pattnaik ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश की जा रही है। पटनायक ने इस तरह की गतिविधियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए धनबल का इस्तेमाल किया जाता है तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ अपराध के समान है। उनके इस आरोप के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल ओडिशा में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, लेकिन मैदान में पांच उम्मीदवार उतरने के कारण मुकाबला बेहद रोचक और अनिश्चित हो गया है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों को क्रॉस-वोटिंग की आशंका भी सता रही है। राज्य की विधानसभा में किसी एक दल के पास चौथी सीट सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, जिससे चुनाव की स्थिति जटिल बन गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव साधारण औपचारिकता नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक परीक्षा बन गया है। बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने विधानसभा परिसर में आयोजित मॉक-पोल सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेता और उसके तीनों उम्मीदवार विधायकों से संपर्क कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर

रहे हैं। पटनायक ने कहा कि लोकतांत्रिक चुनावों में जीत हासिल करने का सही तरीका जनता के समर्थन और विधायकों के विश्वास से होना चाहिए, न कि किसी प्रकार के प्रलोभन या दबाव के माध्यम से। उन्होंने कहा कि यदि विधायकों की खरीद-फरोख्त जैसी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो यह लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर कर देगी। पटनायक के इस बयान ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक Jaya Narayan Mishra ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया है। मिश्रा ने कहा कि भाजपा किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त में शामिल नहीं है और पार्टी केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजद प्रमुख चुनाव से पहले ही हार की आशंका से घिर गए हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है उसे हर चीज पीली दिखाई देती है, उसी तरह बीजद नेतृत्व को हर जगह साजिश ही दिखाई दे रही है। भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवारों में राज्य इकाई के अध्यक्ष Manmohan Samal और वर्तमान राज्यसभा सांसद Sujit Kumar शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री Dilip Ray निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं और उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त बताया जा रहा है। दूसरी ओर बीजू जनता दल की ओर से Santrup Mishra और Dr Datteshwar Hota को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों उम्मीदवारों को कोशिश और वामपंथी दलों का समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। इस तरह से

पांच उम्मीदवारों के मैदान में होने के कारण चुनाव का गणित काफी जटिल हो गया है और हर वोट की अहमियत बढ़ गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि चौथी सीट पर मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प है। यदि विधायकों के बीच किसी भी प्रकार की क्रॉस-वोटिंग होती है तो चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है। इसी संभावना के कारण दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने-अपने उम्मीदवारों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य की राजनीति में यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे आने वाले समय में दलों की राजनीतिक ताकत का भी संकेत मिल सकता है। भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए जय नारायण मिश्रा ने कहा कि कुछ विधायक बीजद से असंतुष्ट हैं और उन्हें भविष्य को लेकर चिंता है। उन्होंने दावा किया कि कई विधायक भाजपा की नीतियों और नेतृत्व से प्रभावित हैं और यही कारण है कि वे अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने का निर्णय ले सकते हैं। मिश्रा ने कहा कि यदि कोई विधायक अपनी इच्छा से मतदान करता है तो उसे खरीद-फरोख्त कहना उचित नहीं होगा। उनके अनुसार लोकतंत्र में हर जनप्रतिनिधि को अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार है। इस राजनीतिक विवाद के बीच बीजद के कुछ नेताओं ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। बीजद विधायक Byomkesh Ray ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री Mohan Charan Majhi विधायकों से संपर्क कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। रे ने कहा कि यदि किसी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की पहल

की जाती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब ओडिशा में लंबे समय बाद इस तरह का प्रतिस्पर्धी चुनाव देखने को मिल रहा है। राज्य में पिछले लगभग बारह वर्षों से राज्यसभा चुनाव बिना किसी बड़े मुकाबले के संपन्न होते रहे हैं, क्योंकि सीटों की संख्या और दलों की ताकत के आधार पर परिणाम पहले से तय हो जाते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं और चार सीटों के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में होने से चुनावी माहौल बेहद रोचक बन गया है। राज्यसभा की ये चार सीटें 2 अप्रैल को खाली हो रही हैं, इसलिए इनके लिए 16 मार्च को मतदान निर्धारित किया गया है। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए लगातार बैठकें और रणनीतिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं। कई दल अपने विधायकों को समूह में रखने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की क्रॉस-वोटिंग की संभावना कम हो सके। ओडिशा की राजनीति में इस चुनाव को केवल राज्यसभा की सीटों तक सीमित नहीं देखा जा रहा है। इसे राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और दलों के प्रभाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि किसी भी पक्ष को अप्रत्याशित सफलता मिलती है तो इसका असर आने वाले चुनावों और गठबंधनों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल आरोप-प्रत्यारोप के बीच राज्य की राजनीति में तनाव का माहौल बना हुआ है।



गरवी गुजरात
हिन्दी



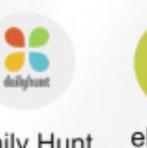
Jio Air Fiber



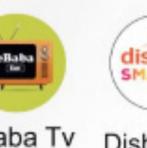
Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

वर्ष 2025 के दौरान राज्य तथा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा क्रमशः 1670 तथा 12920 मामलों का समाधान किया गया

राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से जुड़ी शिकायतों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन से 22700 से अधिक लोगों को मिला मार्गदर्शन

(जीएनएस)। गांधीनगर : एक जागरूक उपभोक्ता सशक्त समाज तथा विश्वसनीय बाजार व्यवस्था का आधार है। विश्वभर में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के विषय में अवगत करने के लिए हर वर्ष 15 मार्च को 'विश्व उपभोक्ता दिवस' मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो तथा उन्हें सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध हों; इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2025 को बात करें, तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा क्रमशः 1670 तथा 12920 मामलों का समाधान किया गया है।



राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन द्वारा 22700 से अधिक उपभोक्ताओं को मिला मार्गदर्शन

गुजरात में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के विषय में शिक्षित करने तथा राज्य सरकार का हेल्पलाइन नंबर 14437 कार्यरत है, जिसमें उपभोक्ताओं को कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल ई-जागृति तथा 1915

हेल्पलाइन के अलावा; राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं से जुड़ी शिकायतों के लिए राज्य सरकार का हेल्पलाइन नंबर 14437 कार्यरत है, जिसमें उपभोक्ताओं को उनसे जुड़ी शिकायतों के विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह हेल्पलाइन

कंज्यूमर्स क्लब के लिए राज्य सरकार करती है वार्षिक 1.25 करोड़ रुपए का खर्च

राज्य के नागरिकों में उपभोक्ता के रूप में जागरूकता बढ़े, राज्य का युवाधन उपभोक्ता सुरक्षा गतिविधियों में जुड़ने को प्रेरित हो और राज्य में उपभोक्ता गतिविधियों को वेग मिले; इस उद्देश्य से कंज्यूमर्स क्लब की योजना शुरू की गई है। हाल में राज्य सरकार द्वारा कुल 2500 कंज्यूमर्स क्लब तैयार किए गए हैं, जिसमें जिलेवार एक समन्वय एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त उपभोक्ता सुरक्षा मंडल कामकाज करता है। राज्य सरकार द्वारा प्रति क्लब 5000 रुपए की वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है, जिसके लिए राज्य सरकार वार्षिक लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च करती है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की थीम : सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता

इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 'सेफ प्रोडक्ट्स, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स' (सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता) थीम अंतर्गत मनाया जा रहा है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह अभियान ऑनलाइन तथा ऑफलाइन विकने वाले जोखिम भरे या असुरक्षित उत्पादों के विरुद्ध कड़े नियम और देखरेख मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर देता है। इसके साथ प्रोडक्ट सुरक्षित है या नहीं; यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार, उद्योगों तथा ग्राहकों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है।

2025 में राज्य तथा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा क्रमशः 1670 तथा 12920 मामलों का समाधान किया गया

गुजरात में वर्ष 2025 के दौरान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 2047 तथा अधीनस्थ जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में 18166 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें से क्रमशः 1670 तथा 12920 मामलों का समाधान किया गया है। इसके अलावा; 2025-26 में आयोजित लोक अदालत द्वारा 246 मामलों में 4.34 करोड़ रुपए से अधिक का आपसी समाधान लाकर समस्या सुलझाई गई है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहाँ पंचायत से पहले लंबित मामलों अथवा कानून की अदालत में प्री-लिटिगेशन स्टेज पर निपटान किया जाता है।

मरुच में मनाया गया 'विकास उत्सव' : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मरुच जिले को 1350 करोड़ रुपए के 139 विकास कार्यों की सौगात दी

▶▶ भरुच से मुख्यमंत्री ने अंकलेश्वर-राजपीपला हाईस्पीड कॉरिडोर और एयर स्ट्रीप फेज-2 सहित कई मेगा परियोजनाओं का शिलान्यास किया

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसा सुदृढ़ आयोजन किया है, जिससे विकास कार्यों के लिए धन की कभी कमी न हो : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▶▶ वर्ष 2001 में राज्य का बजट 36 हजार करोड़ रुपए था, जो आज 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है

▶▶ भरुच में नए जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 2 लाख से अधिक युवाओं के सपने साकार होंगे

▶▶ दुनिया में ग्लोबल केमिकल हब के रूप में विख्यात भरुच जिले के जंबूसर में 1 हजार एकड़ में आकार ले रहा है देश का पहला बल्क ड्रग्स पार्क

▶▶ 1248.57 करोड़ रुपए के 73 विकास कार्यों के शिलान्यास और 102 करोड़ रुपए के 66 विकास कार्यों के लोकार्पण सहित कुल 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शंभे

▶▶ आवेदकों को सरल और सुगम प्रशासनिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा 1.17 करोड़ रुपए के खर्च से नवीनीकृत 4 जनसेवा केंद्रों का लोकार्पण

▶▶ नर्मदा परिक्रमार्थियों के लिए 8 विश्राम हॉल और ग्रामीण स्तर पर 64 नए पंचायत घरों की शंभे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को भरुच जिले के सर्वांगीण विकास को नई गति देने हेतु 1248.57 करोड़ रुपए के 73 विकास कार्यों का शिलान्यास और 102 करोड़ रुपए के 66 विकास कार्यों का लोकार्पण कर भरुच के नागरिकों को कुल अनुमानित 1350.68 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं की शंभे दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसा सुदृढ़ आयोजन किया है, जिससे विकास कार्यों के लिए धन की कभी कमी न हो।

वाली जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उससे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की सुगमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक के सभी क्षेत्रों में हुए ये कार्य भरुच के विकास में अहम साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने अतीत के विकट दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि 1960 में जब गुजरात एक अलग राज्य बना था, तब संसाधनों की कमी थी, दूर-दूर तक विकास की संभावना दिखाई नहीं देती थी। लेकिन, 2001 से श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास की जो राजनीति शुरू की, उससे राज्य आज आत्मनिर्भर बन गया है। वर्ष 2001 में राज्य का बजट केवल 36,000 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। औद्योगिक हब के रूप में उभरे भरुच के विकास को और अधिक तेजी देने के साथ ही भरुच को एयर और रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि भरुच, अंकलेश्वर, दहेज और सायखा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के लिए अंकलेश्वर में एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। अंकलेश्वर-राजपीपला की 44 किमी लंबी सड़क को 760 करोड़ रुपए की लागत से हाई-स्पीड कॉरिडोर में अपग्रेड करने का काम शुरू हो चुका है। इससे स्ट्रेच्यू ऑफ ग्रूमिटी तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स सुविधा के लिए भरुच-नहेज रोड को एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे बनाने का काम भी जगो से चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि कभी भरुच जिला पंचायत का बजट 300 करोड़ रुपए था, जिसके लिए आज एक ही दिन में जिला पंचायत 309 करोड़ रुपए के कार्यों की शंभे दे रही है। विकास की राजनीति और जनहित के विजन का यह जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' जैसे अभियानों को गति देने के उद्देश्य के साथ भरुच में नए जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए 2 लाख से

अधिक युवाओं का सपना साकार होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2030 में जब अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं, तब ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रतिभाशाली नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में ग्लोबल केमिकल हब के रूप में विख्यात भरुच जिले के जंबूसर में एक हजार एकड़ क्षेत्र में देश का पहला बल्क ड्रग्स पार्क आकार ले रहा है। भरुच, नैरंग, राजपारडी और जंबूसर में 50 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाला कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटर सह रेस्ट हाउस स्थानीय व्यापार और आगंतुकों के लिए वरदान साबित होगा। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भरुच और द्वागड़िया में 8 अलग-अलग स्थानों पर विश्राम हॉल के निर्माण से श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा करना और भी आरामदायक बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भरुच को ग्रोथ हब के रूप में सूरत इकोनॉमिक रीजन हब में शामिल किया है और इसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाल ही में 1185 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से विकास की गति के डबल होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सभी लोगों से 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' का संकल्प साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया। भरुच के सांसद श्री मनसुखभाई वसना ने भरुच जिले में अवैध रेत खनन को रोककर भूमिफिशियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कठोर कार्रवाई की प्रशंसा की और कहा कि इस कार्रवाई के दौरान वसुली हुई जुर्माने की राशि से भरुच जिले के विकास कार्यों में आर्थिक सहयोग मिल रहा है, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। इसके साथ ही, भरुच जिले की आंतरिक सड़कों और हाईवे का काम भी बहुत सटीकता और तेजी से हो रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के कारण जिले के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और विस्तार को गति मिली है। गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और

भरुच जिला के प्रभारी मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पानशेरिया ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास की असली परिभाषा गुजरात में शुरू की थी, जिसे आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में ग्राम पंचायत और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास में योगदान दे रहे हैं। श्री पानशेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम और बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय का नारा दिया है, जिसे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सही मायनों में चरितार्थ कर रहे हैं। सरकार हमेशा अंत्योदय के हित में काम कर रही है और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि प्रत्येक योजना का लाभ असली लाभार्थी तक पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री महेशसिंह वांसदाया ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की रूपरेखा दी और जिले में हो रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता वितरित की गई। कार्यक्रम में जलापूर्ति और जल संसाधन मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, विधायक सर्वश्री रमेशभाई मिस्त्री, अरुणसिंह राणा, रिशेशभाई वसावा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती निभूतिबा यादव, जिला कलेक्टर श्री गौरांग मकवाना, जिला विकास अधिकारी श्री योगेश कापसे, सड़क एवं भवन विभाग के मुख्य अभियंता श्री सी.पी. पटेल, जिले के अग्रणी श्री प्रकाशभाई मोदी, पूर्व सांसद श्री भरतसिंह परमार, पूर्व विधायक श्री दुष्यंतभाई पटेल, श्री मावलीसिंह अटोदरिया, जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में जिले के नागरिक मौजूद रहे।

सूरत: चरागाहों की बिक्री के बाद गायें सड़कों पर भटक रही थीं, कलेक्टर ने कार्रवाई की और गायों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराईं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

सूरत का भौगोलिक विस्तार लगातार बढ़ रहा है। सूरत का भूगोल बदल रहा है। इसका कारण वे गाँव हैं जो बढ़ते हुए सूरत में शामिल हो रहे हैं और नए गाँव बन रहे हैं, और यह कहना गलत नहीं होगा कि सूरत एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

शुच्य ट्रुटि विज्ञापन लेकिन शर्मनाक बात यह है कि निगमित गाँवों और उनमें स्थित चरागाहों को

ग्राम प्रशासक स्वयं बड़े-बड़े लोगों या राजनीतिक विचारधारा वाले बिल्डरों को बेच रहे हैं।

हिंदू राष्ट्र की प्रशंसा करने वाले और उनका समर्थन करने वाले भ्रष्ट शासकों की प्रशंसा करने वाले इन हिंदुत्ववादी ठेकेदारों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है ? जहाँ चरागाह बेचना और चरागाह लेना अपराध है,

वहाँ भी खरीदार और विक्रेता दोनों ही अपराधी हैं।

बिल्डरों ने गायों के चरागाह को अपने कंधों पर उठा लिया

एक ओर, कुछ ग्रामीण प्रशासकों और अधिकारियों के कारण गाँवों की चरागाह भूमि

बेची जा रही है, वहीं दूसरी ओर, शहरों की सड़कों पर आवागाम घूमती रहती हैं, जिससे पैदल चलने वालों की जान को खतरा होता है।

वहीं दूसरी ओर, ऐसी ही गाय को बचाने की कोशिश में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या उनमें की मृत्यु हो जाती है। कई मामलों में

गाय की मृत्यु की खबर अखबारों में भी छपी है।

प्रशासन से नागरिकों की लगातार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है।

इसका मुख्य कारण यह है कि गायों के लिए बनाए गए चरागाह बेचे जा रहे हैं, जिसके कारण गायें गरीब हो जाती

हैं और अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर

एक ओर हम कहते हैं कि चींटियाँ अनाज के समान होती हैं और हाथी पत्थर के समान, लेकिन यहाँ,

इन भूखी और अस्ताव्य गायों का ऐसा सौभाग्य नहीं है, इसलिए माँ गाँव

अपना पेट भरने के लिए सड़क पर पड़े कचरे या कूड़े को खाने को मजबूर है।

इस प्रकार, गाँव के तथ्यांकित प्रशासकों,

द्वारा राजनीतिक दिग्गजों की मदद से गाँव की चरागाह भूमि पर चरने वाले साँडों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और कलेक्टर को चरागाह भूमि को खोलकर सरकार और ग्रामीणों के सहयोग से

हरी घास और मुलायम घास लगाने की योजना बनानी चाहिए और चारे का उत्पादन शुरू करना चाहिए। और

गौशालाओं में ऐसी घास उपलब्ध कराने से सड़कों पर भटकती गायों की भूख

अनाथ होकर सड़क पर भटकने लगती है, और

कुछ लालची आवाग लोग इसका फायदा उठाते हैं। और ऐसे लोग

रात में तिपटिया या चार पहिया वाहनों में आते हैं और अनाथ गायों को उठाकर कसाईखाने में बेच देते हैं।

तो यहाँ सवाल उठता है कि एक तरफ हम गोभक्तों और हिंदू राष्ट्र

की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में खुलेआम गायों की हत्या होते

देख हम घोर चुप्पी साधे रहते हैं। ऐसे में क्या हम को राष्ट्रीय पक्षी मौर की तरह

पवित्र और पूजनीय राष्ट्रीय गौमाता घोषित क्यों नहीं किया गया है ?

सरकार ऊपर से नीचे तक दोहरी गाय की मृत्यु की खबर अखबारों में

भी छपी है। प्रशासन से नागरिकों की लगातार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है।

इसका मुख्य कारण यह है कि गायों के लिए बनाए गए चरागाह बेचे जा रहे हैं, जिसके कारण गायें गरीब हो जाती

हैं और सरकार को उन

जमीनों को वापस लेना चाहिए। और ऐसी जमीनों पर दबाव कम करके

ऐसे विक्रेताओं और खरीदारों पर किसी प्रकार की पबंदी क्यों नहीं

लागाई जानी चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई करना और उन्हें जेल भेजना

जरूरी है। क्योंकि चरवाहों और आवाग लोगों को पकड़ने

गए पुलिसकर्मियों के बीच झड़पों जैसी गंभीर घटनाओं का मूल कारण

भी चरागाह भूमि की बिक्री ही है। और अंत में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है

कि चरागाह भूमि पर चरने वाले साँडों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और

कलेक्टर को चरागाह भूमि को खोलकर सरकार और ग्रामीणों के सहयोग से

हरी घास और मुलायम घास लगाने की योजना बनानी चाहिए और चारे का

उत्पादन शुरू करना चाहिए। और गौशालाओं में ऐसी घास उपलब्ध कराने

से सड़कों पर भटकती गायों की भूख अनाथ होकर सड़क पर भटकने लगती है, और

कुछ लालची आवाग लोग इसका फायदा उठाते हैं। और ऐसे लोग

रात में तिपटिया या चार पहिया वाहनों में आते हैं और अनाथ गायों को उठाकर कसाईखाने में बेच देते हैं।

तो यहाँ सवाल उठता है कि एक तरफ हम गोभक्तों और हिंदू राष्ट्र

की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में खुलेआम गायों की हत्या होते

देख हम को राष्ट्रीय पक्षी मौर की तरह पवित्र और पूजनीय राष्ट्रीय गौमाता घोषित क्यों नहीं किया गया है ?

सरकार ऊपर से नीचे तक दोहरी गाय की मृत्यु की खबर अखबारों में

भी छपी है। प्रशासन से नागरिकों की लगातार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है।

इसका मुख्य कारण यह है कि गायों के लिए बनाए गए चरागाह बेचे जा रहे हैं, जिसके कारण गायें गरीब हो जाती

“सूरत उमरवाड़ा भूमि विवाद में छगनलाल मेवाड़ा बनाम नरेश अग्रवाल और भूमि हथियाने वाली समिति”

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर, उमरवाड़ा, शहर सर्वेक्षण संख्या 2177, टीपी योजना संख्या 8 (उमरवाड़ा), अंतिम भूखंड संख्या 83, जिसका क्षेत्रफल 11209 वर्ग मीटर है। इस स्थल के मूल स्वामी-कब्जेदार, जारवाद मुल्तानी पंच कंत्रिलान ट्रस्ट के न्यायियों ने 31/12/2014 के एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से छगनलाल डी. मेवाड़ा को स्थायित्व अधिकार सौंप दिए थे और तब से छगनलाल मेवाड़ा इस स्थल के स्वामी-प्रशासक के रूप में इस्का प्रबंधन कर रहे हैं। इस जमीन पर कब्जा करने के लिए नरेश अग्रवाल नामक व्यक्ति ने अपराध किया है और उसने सूरत शहर के वर्तमान कलेक्टर छगनलाल मेवाड़ा और सौरभ पार्थी के खिलाफ गुजरात भूमि हड़पने (निषेध) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के तहत किसी भी तरह से जमीन पर कब्जा किया है। 29/07/2025 को, भूमि हड़पने समिति ने



भूमि हड़पने समिति के समक्ष पेश किया गया। छगनलाल मेवाड़ा अपने वकील के माध्यम से भूमि हड़पने समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। लेकिन भूमि हड़पने की समिति, माने भंग हो चुकी हों, ने छगनलाल मेवाड़ा और उनके वकील की बात पॉच मिनट तक भी संतोषजनक ढंग से नहीं सुनी और समिति के सदस्यों ने यह कहते हुए मामले को सुनने से इन्कार कर दिया कि उन्हें इसकी जानकारी है। उस दिन उपस्थित सभी पक्ष कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठे थे। इससे क्या संकेत मिलता है कि सूरत कलेक्टर के कार्यालय में केवल हेमंत अग्रवाल, नरेश अग्रवाल और नटवर मुरलीवाल हरालालका ही ऐसी कार्यालय में बैठे थे ? जब सभी पक्ष बाहर बैठकर अपनी



बारी का इंतजार कर रहे थे, तो समिति को हेमंत अग्रवाल ने क्या दिलचस्पी थी ? और 07/08/2025 को छगनलाल मेवाड़ा के वकील भूमि हड़पने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया मरवी गुजरात 1 । शुच्य ट्रुटि एजेंसी छगनलाल मेवाड़ा ने जारवाद मुल्तानी पंच मस्जिद स्थल के ट्रस्टियों के साथ एक समझौते के माध्यम से कानूनी रूप से भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है, यह तथ्य साक्ष्य सहित भूमि हड़पने वाली समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, और भूमि के मूल मालिकों ने भूमि हड़पने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, तो छगनलाल मेवाड़ा के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष द्वारा

शिकायत दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि छगनलाल मेवाड़ा हेमंत अग्रवाल को नहीं जानते हैं, तो क्या वे उन्हें जानते हैं या नरेश अग्रवाल को नहीं जानते हैं ? इस प्रकार, भूमि हड़पने वाली समिति ने हेमंत नरेश अग्रवाल के साथ मिलीभगत करके गलत तरीके से मामला दर्ज किया है। जिसके कारण छगनलाल मेवाड़ा को जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। छगनलाल मेवाड़ा द्वारा 12/08/2025 को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति अपील (आपेथिक) (एस) 11907/2025 दायर की गई थी। कलेक्टर के दिनांक 16/07/2025 के नोटिस में निर्वाधता जारी की गई है। उमरवाड़ा स्थित इस भूमि के संबंध में, नरेश अग्रवाल (कुवेजी एंटरप्राइज) के सझेदार नटवरलाल मुरलीवाल हरालालका ने उमरवाड़ा स्थित उपरोक्त भूमि का कब्जा लेने के लिए सूरत के प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की अदालत में पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि यदि कब्जे के आधार पर मांग नहीं की गई है, तो उस भूमि का कब्जा सौंपने के लिए पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती। तदनुसार, 20/07/2018 को यथिका संख्या 20/2015 खारिज कर दी गई।

इस प्रकार, उपरोक्त अदालत का आदेश इस तथ्य को सिद्ध करता है कि नरेश अग्रवाल और नटवरलाल हरालालका इस भूमि पर कब्जे में नहीं थे। उमरवाड़ा स्थित इस भूमि को सूरत कलेक्टर जयप्रकाश शिवहर के कार्यकाल के दौरान गलत तरीके से एनए (गैर-कानूनी घोषित) करने की अनुमति दी गई थी। इस भूमि को एनए घोषित करने से पहले आवेदन से पहले विभिन्न विभागों की राय ली गई थी। साथ ही, नियमों के अनुसार, एनए अनुमति उस स्थिति में नहीं दी जा सकती जहाँ एनए अनुमति से पहले कोई अदालती मामला लंबित न हो। इस भूमि पर अदालती मामला चल रहा होने के बावजूद एनए अनुमति दी गई थी और एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी अदालती मामला लंबित नहीं है। इस दौरान, नामदार राज्य विभाग में एक पुरीक्षण आवेदन लंबित था, नामदार गुजरात उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित था और गन्ती कार्यवाही के कारण प्राप्त कृषि भूमि को केशवभाई घुसाभाई रामोलिया ने पुराने स्वरूप में पतित करने की कार्रवाई करने के बाद बेच दिया था। नामदार सिविल न्यायालय में पुरीक्षण ज्ञापन संख्या 288/2014 के तहत एक दवा था। उप कलेक्टर के समक्ष एक लंबित मुकदमा दर्ज किया गया है, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय में यथिका संख्या 4096/2015 दायर की गई है। केशवभाई घुसाभाई रामोलिया ने 15/06/2013 को एनए अनुमति प्राप्त करने के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत किया था कि वह किसी भी दीवानी मुकदमे, अन्य प्रकार के मुकदमे में नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई विवाद किसी भी प्राधिकरण/अधिनियम, न्यायाधिकरण या न्यायालय में लंबित नहीं है। लंबित अदालती मामलों के बावजूद और इस संबंध में तत्कालीन कलेक्टर को लिखित शिकायत के बावजूद, कलेक्टर जयप्रकाश शिवहर ने एनए अनुमति नहीं दी है और न ही अनुमति रद्द की है। रामोलिया केशवभाई घुसाभाई ने गैर-कृषि क्षेत्र के लिए अनुमति हेतु आवेदन किया है। 15 इंद्रप्रस्थ सोसाइटी, मागीव ने 15/03/2014 को आवेदन किया था एनए अनुमति देने से पहले, सरकार के विभिन्न विभागों की राय प्राप्त की जाती है। कलेक्टर कार्यालय से दिनांक 16/09/2011 को पर संख्या LAQ/Vashi/2386 के माध्यम से दिनांक 16/01/2013, उप कलेक्टर नगर प्रांत सूरत से दिनांक 13/12/2011, मामलतदार नगर से दिनांक 14/11/2011, जिला आर्पूरी अधिकारी से दिनांक 27/09/2011, सहायक

नगर योजनाकार/शहरी विकास प्राधिकरण से दिनांक 17/06/2011 के पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि जब आवेदन के दिनांक 15/03/2014 को एनए अनुमति के लिए आवेदन किया था, तो उपर्युक्त कलेक्टर जयप्रकाश शिवहर ने भ्रष्टाचार किया और एनए (नेशनल लाइसेंस) की अनुमति दी, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। इस गलती के संबंध में कलेक्टर जयप्रकाश शिवहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सरकार ने अनुरोध के अनुसार सभू को प्रस्तुत किया है। नरेश अग्रवाल ने उसी की जमीनों के लिए जो पैसा खरीदा था, लोगों को भुगतान नहीं किया है, इसमें कई एनआरआई भी शामिल हैं। नरेश अग्रवाल ने अपने सहायकों को भी रिहा नहीं किया है और इस सब पैसे का भुगतान नहीं करने और विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए, उन्होंने सरीली स्थित भारत कैसर अस्पताल के पास कुवेजी वैंलेटाइन प्रोजेक्ट के कार्यालय में अक्षय की गौलियां खाने को बुकेजी पुत्र इस्से काफ़ी हंगामा मच गया। 29/09/2023 को, अक्षय की गौलियां खाने वाले कुवेजी पुत्र के बिट्टर नरेश अग्रवाल ने छगनलाल मेवाड़ा के खिलाफ 5.41 मिपट का आर्डियो वायल

किया और छगनलाल मेवाड़ा के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। कैमलाल मेवाड़ा अस्थायतन एक सम्मानित व्यापारी और सामाजिक नेता हैं। उन पर निराधार आरोप लगाकर उनके व्यापार और रोजगार को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही, इस दौरान उनके परिवार को भी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है। नरेश अग्रवाल द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से उनके व्यापार पर भी असर पड़ा है। हेमंत नरेश अग्रवाल और भूमि हड़पने वाली समिति ने ऐसा कृत्य किया है जिससे मेवाड़ा में लोगों का विश्वास कम